मुक्त पाठ्य सामग्री

2016-17

कक्षा **ग्यारहवीं**

अर्थशास्त्र

विषय	पृष्ठ
1. चीन की एकल बालक नीति	1
2. आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी–निवेश (एफ.डी.आई.) की भूमिका	13

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिक्षा केन्द्र, 2, समुदाय भवन, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092, भारत

मुक्त पाठ–आधारित मूल्यांकन 2016–2017

अर्थशास्त्र (030) कक्षा–ग्यारहवीं

विषय–1 : चीन की एकल बालक नीति

शिक्षण उद्देश्य

- चीन की एकल बालक नीति की अवधारणा तथा नतीजों को समझना।
- चीनी सरकार द्वारा एकल बालक नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार कारणों को समझना।
- चीन की एकल बालक नीति के परिणामों को विस्तृत करना।
- चीन की एकल बालक नीति के परिणामों को समझने के लिए।
- कार्यान्वयन से लगभग 45 साल बाद नीति को वापिस लेने के पीछे के कारणों का विश्लेषण करना।
- पिछले पाँच दशकों में भारत चीन की जनसंख्या वृद्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

पाठकों के लिए टिप्पणी

अध्ययन के मामले के साथ–साथ कक्षा में चर्चा तथा विश्लेषण (शिक्षकों तथा छात्रों) के द्वारा किया जाना चाहिए। पाठक एक बुद्धिशीलता सत्र में निम्नलिखित पर चर्चा कर सकते हैं।

- अवतरण अध्ययन के उद्देश्य।
- अवतरण में शामिल अवधारणाएं।
- वास्तविक जीवन स्थितियों में अवधारणाओं का व्यवहारिक प्रयोग।
- अवतरण या इसी तरह की परिस्थितियों के उदयन।

मुक्त पाठ–आधारित मूल्यांकन 2016–2017

अर्थशास्त्र (030) कक्षा–ग्यारहवीं

विषय 1 : चीन की एकल बालक नीति

सारांश

चीन हमेशा अपनी अविश्वसनीय नीति निर्माण तथा उनके अकल्पनीय कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है। चाहे महान श्रमजीवी सांस्कृतिक क्रान्ति हो या ग्रेट लीप फॉरवर्ड या विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति हो चीन हमेशा अपने सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए एकल पार्टी कम्युनिस्ट शासन के तहत दूरगामी कदम उठाता है। ऐसा ही एक कदम अत्याधिक बात और गरमागरम बहस नीति कदम 'एकल बालक' वर्ष 1978 के बाद से चीन द्वारा अपनाया (जो हाल में ही चीन सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 2015 को वापिस लिया गया।) सरकार द्वारा एकल बालक नीति का विनष्टीकरण असंख्य दम्पत्तियों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया है। कुछ अर्थशास्त्री इस विनष्टीकरण की सफलता के बारे में संशयशील है क्योंकि वर्तमान उच्च निर्वाह खर्च तथा मानसिकता का सामना करना चीनी दम्पत्तियों के लिए सरल नहीं होगा। जो अभी तक कई वर्षों से तीन सदस्य परिवार में रहे हैं। यह पाठ्य चीन की वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ समझने तथा उनके विश्लेषण करने का एक प्रयास है इसके अलावा भारत तथा चीन की जनसंख्या वृद्धि का एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाएगा।

सरकार द्वारा एकल बालक नीति का समापन

विन–ली (एक काल्पनिक पहचान) चीन की सरकार द्वारा एकल बालक नीति को वापिस लेने के बारे में अखबार में पढ़ रहा था और कोशिश कर रहा था इस घटना के साथ इतिहास फिर से लिखा जा रहा है। वह बीजिंग की राजधानी के शहर में उन भाग्यशाली (अभाग्यशाली) मध्यम आयु वर्ग के शहरी निवासियों में से एक है जो अपने आस–पास कभी भी भाई–बहन की संगति में नहीं रहा। 1978 में चीनी सरकार द्वारा एकल बालक नीति को कार्यान्वयन करने के लिए धन्यवाद। इसी तरह साल दर साल, दशक दर दशक, पीढ़ी दर पीढ़ी बिना भाई–बहन के लोग अपने जीवन और परिवार में आगे बढ़ रहे हैं।

एकल बालक नीति को लेकर कुछ वैद्य आर्थिक तर्क भी हो सकते हैं जैसे (नियंत्रित प्रजनन दर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना आदि) परन्तु करोड़ों दम्पत्तियों तथा बच्चों के जीवन में उत्पन्न हुए उस 'रिक्त स्थान' के लिए कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जो उन्होंने अपने भाई-बहन ना होने के कारण अनुभव किए हैं। इसके अलावा, इस नीति ने चीन में बढ़ती हुई बुर्जुग निर्भर आबादी जैसी नई समस्याओं को जन्म दिया है। उन्होंने पूर्वव्यापी प्रक्रिया पर विचार शुरू किया कि यह सब कैसे और कहाँ से शुरू हुआ।

माओ जितुंग (1893-1976), चीन के दिग्गज नेता ने हमेशा ये माना कि आबादी वाला चीन अपने क्रान्ति आंदोलन के पहले भाग के दौरान एक 'समृद्ध चीन' को जन्म दे सकता है। 1950 और 1960 के दौरान चीन की प्रजनन दर सबसे अधिक असाधारण तरीके से उच्च बनी रही। इसलिए आबादी तेजी से बढ़ने लगी। दुर्भाग्य से, वहाँ 1959-1961 के दौरान एक भयावह अकाल पड़ा जो चीन की आबादी की प्रजनन दर और विकास दर को काफी नीचे लाया। बहुत ही रूढ़ीवादी अनुमानों के अनुसार कृषि उत्पादन में विकास और भोजन की कमी के कारण 20,000,000 (20 लाख) लोगों की मृत्यु और 30 लाख असामयिक मृत्यु हुई। हालांकि यह अनुकरण 1960 दशक के अन्तिम कई वर्षों में तीव्रता से ऊपर आने वाले जन्म दर के द्वारा किया गया। साल 1970 में चीन की आबादी 800 मिलियन को पार कर गई और राज्य परिषद (चीन के मंत्रिमंडल) को जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी से आई कमी के लिए बुलाया। परिणामस्वरूप चीन की पीपुल्स रिपब्लिक ने 1971 में अपनी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। जिसके निम्नलिखित दो मुख्य कारण थे।

1. जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी से वृद्धि और,

2. जनसंख्या में वृद्धि की दर के अपेक्षाकृत धीमी गति से खाद्य आपूर्ति विकास।

1975 में, यह इस नारे के साथ वापिस आया 'बाद में लंबे समय तक और कम' और आग्रह किया गया कि शहरी दम्पत्ति दो से अधिक बच्चे ना करें और ग्रामीण दम्पत्तियों के लिए अधिकतम तीन की संख्या सीमित की गई।

A government sign in Tangshan Township: "For a prosperous, powerful nation and a happy family, please practice family planning."
Source: Tangshan Province, Township Authority

एकल बालक नीति 1978 में ड़ेंग जियाओपिंग, चीन के खुले द्वार की नीति के पिता द्वारा चीन की तेजी से बढ़ रही आबादी को रोकने के प्रयास में पेश की गई। 1980 की शुरूआत में चीन अधिकारी इस नीति के कार्यान्वयन में इतने प्रवृत्त थे कि जो लोग इनका पालन नहीं कर रहे थे उनके साथ प्रोत्साहन, जबरन गर्भपात, शिशु हत्या और सख्त दंड जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया। हालांकि, 1984 में ग्रामीण परिवारों को कुछ निश्चित आधार पर छूट की घोषणा की थी। वर्ष 2001 में चीनी सरकार ने इस नीति के विकेन्द्रीयकरण की अनुमति दी तथा उन परिवारों पर जुर्माना एवं दण्ड अधिरोपित करने के लिए स्थाई सरकारों को अधिकार दिए जहाँ एक से अधिक बच्चे थे।

वर्ष 2006 को इस नीति के 'अन्त के प्रारम्भ' के तौर पर देखा जाता है। कुछ प्रान्त जहां श्रम शक्ति कम हो रही थी वहां ऐसे दम्पत्तियें को दो बच्चे करने की अनुमति प्रदान की गई जो स्वयं अपने माता–पिता के इकलौते बच्चे थे। वर्तमान में 29 अक्टूबर 2015 को इस नीति को विनिष्ट करने का प्रारम्भ किया गया।

एकल बालक नीति के परिणाम

चीन के अधिकारियों के अनुसार यह नीति एक अत्यंत सफल प्रयोग रही है। एक अनुमान के अनुसार, 1960 की पहली छमाही में औसत प्रजनन दर प्रति महिला 6 बालकों की थी, जिसके कारण चीन में

जनसंख्या विस्फोट का प्रारंभ हुआ। 1960 के दशक के अंत तक चीन की जनसंख्या 800 मिलियन तक पहुँच गयी थी। जनसांख्यिकी विशेषज्ञों के अनुसार चीन में अभी तक दो 'बेबी बूम' अनुभव किए हैं, पहला मुक्तियुद्धि (Liberation war) के बाद तथा दूसरा 1960 के Great leap forward के बाद। (Baby Boom से तात्पर्य उस अवधि से है जिसमें जन्म दर में अत्यंत तेजी से वृद्धि होती है।)

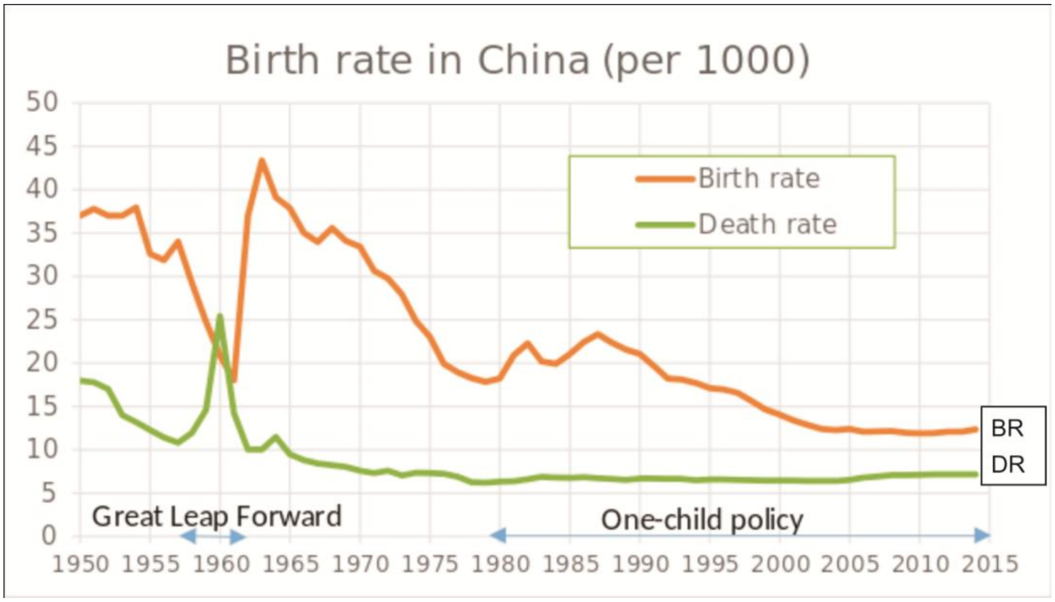

स्रोत : चीन की वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट, 2014, अध्याय-2, *stats.gov.cn*

उक्त ग्राफ, स्पष्ट रूप से उन आकाल वर्षों की अवधि को प्रदर्शित करता है जिसमें मृत्यु दर जन्म दर से अधिक थी तथा उसके बाद निरंतर रूप से मृत्यु दर कम होती गयी थी। 1978-2011 के बीच एकल बालक नीति के प्रत्यक्ष प्रमाण भी इस ग्राफ से स्पष्ट होते हैं। जन्म तथा मृत्यु दर के बीच घटता हुआ अंतर GLF के उपरांत चीन की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी का सूचक है। चीन के अधिकारियों का दावा है कि 1979-2011 के बीच लगभग 400 लाख बच्चों के जन्म को रोका गया है। कुछ जनसांख्यिक विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार की गिरावट का होना निश्चित था, क्योंकि चीन की 'Open door policy' (खुले द्वार की नीति) के कारण शहरीकरण तथा औद्योगिकरण में तेजी से वृद्धि हो रही थी। चीन में प्रजनन दर के लगभग आधा होने के कारण चीन की जनसंख्या वृद्धि दर में काफी गिरावट देखी गयी है। National Geographic के Aileen Clark की रिपोर्ट के अनुसार चीन की वर्तमान जन्म दर (2.1%) अपनी प्रतिस्थापन दर से काफी कम है। इस नीति को प्रथम तथा सबसे बड़ा नकारात्मक परिणाम चीन की तेजी से बढ़ती हुयी वृद्ध जनसंख्या के रूप में सामने आया है।

'United Nations Department of Economic & Social Affairs' द्वारा संचालित एक अध्ययन (चीनी सरकार द्वारा संचालित एकल बालक नीति को रद्द करने से पहले) में यह पूर्वानुमान लगाया गया कि 65 साल की उम्र से अधिक नागरिकों की संख्या 2030 तक बढ़ कर 219 मिलियन हो जाएगी जो कि 2050 तक चीनी आबादी का लगभग 25: होगी। यह चीन में चलती आ रही 'श्रम शक्ति की कमी' में एक विशेष भूमिका निभाएगा। चीन में अधिकारियों को उम्मीद है कि जनसंख्या नियंत्रण में छूट के साथ, इस प्रचलित श्रम शक्ति कमी को कुछ महत्वपूर्ण स्तर तक नीचे लाया जा सकता है।

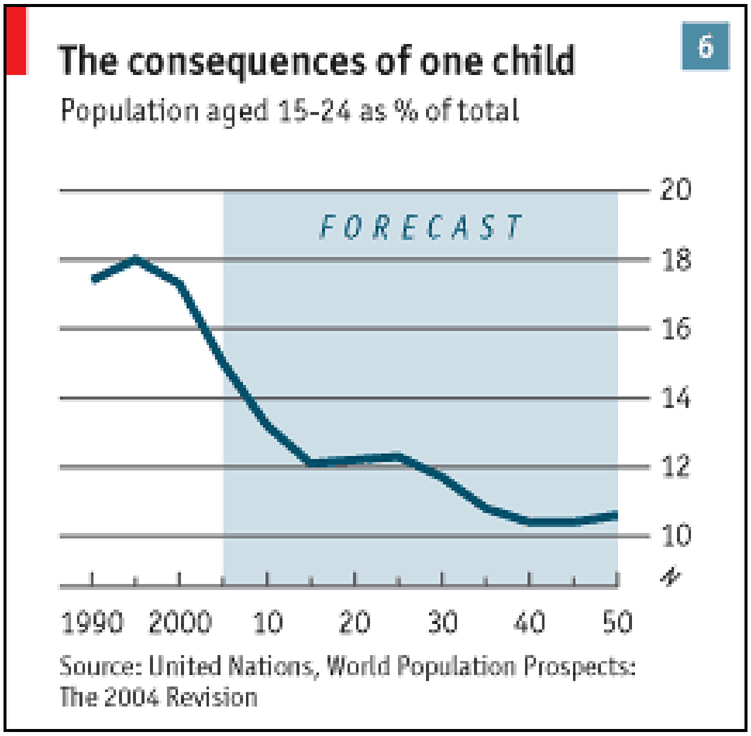

स्रोत : विश्व जनसंख्या संभावनाएँ : 2004 संशोधन, संयुक्त राष्ट्र

हालांकि कुछ जनसांख्यिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अब तक चीन में एकल बालक नीति के मामले में बहुत अच्छी तरह से काम किया और अब इसी नीति को रद्द करने में बहुत देर हो चुकी है। यदि चीन में प्रति महिला 2 बच्चे के हिसाब से जन्म दर में अचानक वृद्धि आती है (संभावना है जो कि बहुत अंधकारमय है) तो भी यह मध्य 2030 या 2040 में कुछ ठीक हो पाएगा जो कि चीन की श्रम शक्ति में कुछ वृद्धि कर सके। सूचनाओं के अनुमान के मुताबिक, उस समय तक अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं खासकर भारत चीन से आगे निकल जाएगा। कुछ अर्थशास्त्रियों ने पहले से ही यह भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है कि भारत दुनिया के विकास का आगामी इंजन (साधन) है।

आज चीन की आबादी में बच्चों के संगठन का हिस्सा बहुत छोटा और बड़ी उम्र के लोगों का समूह बढ़ रहा है। चीन कम प्रजनन और कम जनसंख्या वृद्धि के एक चरण के लिए उच्च प्रजनन, उच्च मृत्यु दर और कम प्राकृतिक विकास के चरण से बदल गया है। वास्तव में चीन अब 'Post Transition Society' में प्रवेश कर गया है जहां जीवन प्रत्याशा (उम्मीदें) नई ऊंचाईयों पर पहुँच गई हैं, प्रजनन क्षमता में गिरावट आई और बुजुर्ग लोगों की जनसंख्या क्षितिज पर है।

Source: China's One-Child Policy and Pension Issues, Luijie, China Daily

श्रम की समस्या के अलावा चीन एक अद्वितीय और अजीब समस्या का भी सामना कर रहा है। अर्थात् 4–2–1 की समस्या। यह समस्या एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक परिवार में 'एक ही बच्चा' है जिसे बिना भाई, बहन की की मदद के अपने माता–पिता और दादा–दादी की जिम्मेदारियों को संभालना है। आप स्पष्ट रूप से 4–2–1 की इस समस्या को कार्टून की सहायता से समझ सकते हैं। 2015 में चीनी नागरिकों का अनुमानित आकार 200 मिलियन से अधिक था जिनमें अधिकतम लोगों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक थी। जिसने अपने परिवार की जरूरतों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ–साथ परिवार के छः बुजुर्ग लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए व्यय में वृद्धि की मांग को बढ़ाया।

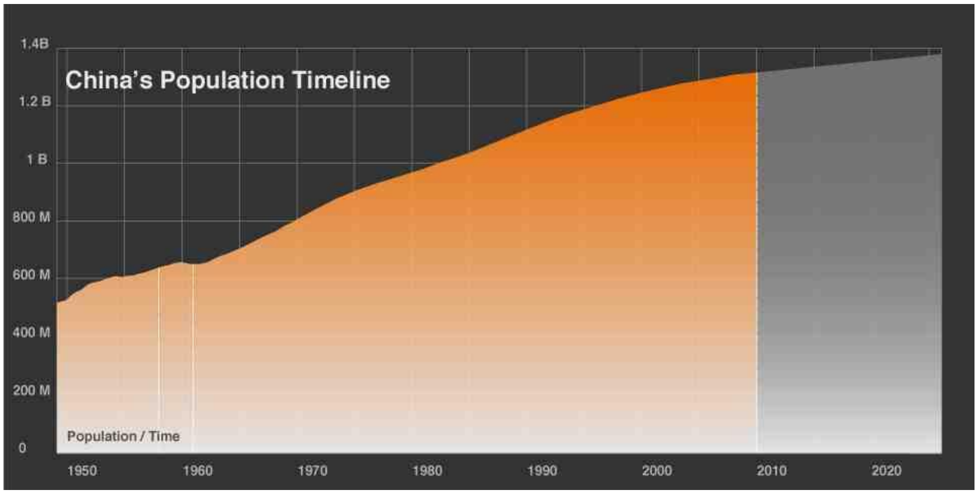

Source: A Guide to China's One Child Policy, Brendon

आधार रेखा यह है कि एकल बालक नीति ने चीन की जनसंख्या वृद्धि को धीमा कर दिया है। इसके बिना, उनकी आबादी आज वर्तमान स्तर की तुलना में कहीं अधिक होगी। एकल बालक नीति का एक अन्य संभावित परिणाम जीवन प्रत्याशा (उम्मीदों) में सुधार हुआ है। आरम्भिक 1950 और 1970 के बीच में हर साल चीन में जीवन प्रत्याशा वृद्धि दर इसी तरह, बेहतर Health Care से मृत्यु दर में काफी गिरावट आई।

चीन, भारत के समान ही एक ऐसा देश है जहां पारम्परिक दृष्टिकोण के साथ लड़कियों की बजाय लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। पिछले कुछ वर्षो में जनसांख्यिकीय डाटा से पता चला है कि एकल बालक नीति ने देश में पहले से विद्यमान वर्तमान विषम लिंग अनुपात को बढ़ा दिया है। एक अनुमान के मुताबिक, देश में महिलाओं से 32-36 मिलियन पुरुष अधिक हैं। चीनी सरकार ने यह बात स्वीकार की है कि पुरुषों की बढ़ती हुई जनसंख्या अब एक सामाजिक समस्या का रूप ले चुकी है, जहाँ विवाह-योग्य लड़कों / पुरुषों की संख्या खतरनाक दर से बढ़ रही है जिस कारण सामाजिक अपराध तथा अशांति में इजाफा हुआ है। विभिन्न शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि 1970 से (एकल बालक नीति के पश्चात) कन्या भ्रूण हत्या तथा कन्या परित्याग के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि 2005 में चीन ने कन्या भ्रूण हत्या को गैरकानूनी घोषित कर दिया था, परन्तु इस कानून को अमली जामा पहनाने में कई प्रकार की समस्यायें सामने आयी हैं।

एकल बालक नीति का समापन - कारण व प्रभाव

विन-ली अभी सोच ही रहा था कि नौकर चाय का एक कप उसे पकड़ा गया, तथा ली चाय का आनन्द लेता हुआ अखबार के उस लेख को आगे पढ़ने लगा।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी Xinhua News के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की विज्ञप्ति के अनुसार यह फैसला "जनसंख्या के संतुलित विकास" में सुधार के लिए लिया गया है। इसका स्पष्ट संदर्भ विषम लिंग अनुपात को कम करना तथा वृद्ध जनसंख्या पर नियंत्रण करने से है। UN के एक अनुमान के अनुसार चीन 2030 तक अपनी क्रियाशील जनसंख्या में से 67 लाख व्यक्तियों को खो देगा, जिसका निश्चित रूप से समाज, अर्थव्यवस्था और सरकार के संसाधनों पर भारी प्रभाव पड़ेगा।

कुछ विद्वानों के अनुसार, एकल बालक नीति के समापन से किसी भी प्रकार के Baby Boom के तुरंत अपेक्षा करना सही नहीं होगा क्योंकि चीन की प्रजनन दर पिछले कुछ समय से लगातार गिर रही है। इस नीति पर पिछले कुछ नियंत्रणों का जनसंख्या पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। चीन की वर्तमान युववा पीढ़ी छोटे परिवार की मानसिकता में बंधे हुए है, जिसे तोड़ पाना आसान नहीं होगा।?

Credit Suisse की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस नीति के समापन से चीन में प्रति वर्ष 3-6 मिलियन नवजात बच्चों की जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। इस रिपोर्ट के अनुसार एकल बालक नीति ने चीन की जनसंख्या को क्षतिग्रस्त किया है परन्तु अब इसके समापन के बाद व्यापार वृद्धि में अरबों की संभावनायें उत्पन्न हो सकती हैं। "संभावित जनसंख्या" आने वाले समय में भोजन, कपड़ा, घर, यातायात, नेटवर्क आदि सभी चीजों की मांग करने वाली है। तथा दीर्घ काल में यह वस्तुओं और सेवाओं की मांग को निश्चित रूप से बढ़ावा देगा।

भारत तथा चीन की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन

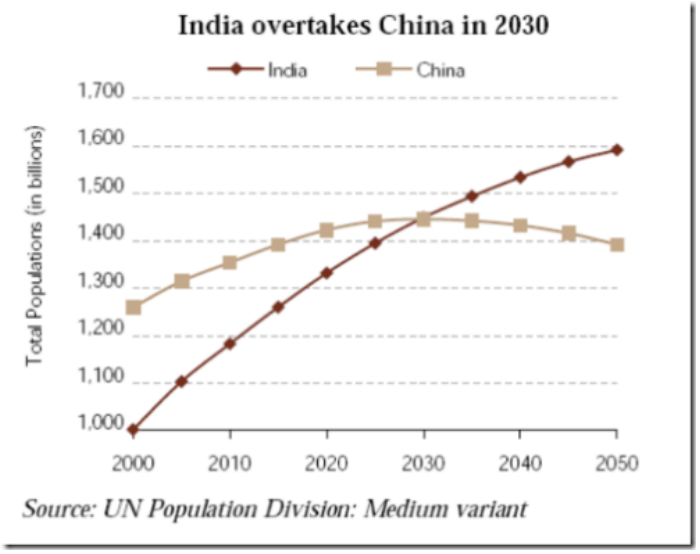

Source: United Nation, Population Division: Medium Variant

विन–ली (Win–li) की आँखें एक और लेख पर भी थी जो दो पड़ोसी देशों भारत और चीन की जनसांख्यिकी डेटा की तुलना करता है। वह अकसर सोचता है कि कैसे दुनियाभर के अर्थशास्त्री बेहद दिलचस्पी से एक ग्रह के दो बड़े देशों के बीच तुलना करते हैं और जिसका सबसे विशेष कारण GDP और जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि है। वे जनसांख्यिकी के लिए भी अच्छे अध्ययन मामले हैं। वर्तमान परिदृश्य में जब चीन दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। और भारत घनिष्ठ रूप से 1.40 अरब इसके पीछे है। और 1.28 बिलियन (लगभग) लोग क्रमशः इन देशों में रह रहे हैं। एक साथ संयुक्त ये राष्ट्र विश्व की आबादी का लगभग 37% संभाले हुए हैं और एशियाई महाद्वीप की कुल आबादी का 61%, निस्संदेह ये आंकड़े विलक्षण हैं।

यह नवम्बर 1970 से चीन द्वारा अपनाई गई एकल बालक नीति की वास्तविकता के खिलाफ विद्यमान है और अब भारत भी पिछले चार–पाँच दशकों से अपनी सोशल इंजीनियरिंग के मॉडल के उपकरण का उपयोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए कर रहा है। भारत (1.2%) की जनसंख्या वृद्धि दर चीन (0ण्5%) की तुलना में अधिक है। और इसके जिम्मेदार दोनों देशों के बीच जल्दी से जनसंख्या की नीचे आती संकुचित खाई है। चीन ने वर्ष 1982 में अपनी 1 बीएन आंकड़ों को पार किया जबकि भारत ने 1998 में। और वर्ष 2033 तक 1.5 बीएन के आंकड़ों को पार करने की उम्मीद है।

जनसंख्या (जनसांख्यिकीय लाभांश) – भारत के लिए मतवाला आर्शीवाद

भारत के प्रधानमंत्री अकसर 'जनसांख्यिकीय लाभांश' जैसे उद्धृत शब्द का उपयोग करते हैं जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है और आने वाले कुछ दशकों में जोड़ता रहेगा। जो हम विकास दर देख रहे हैं उनके मुख्य कारणों में से एक 'युवा भारतीय' है।

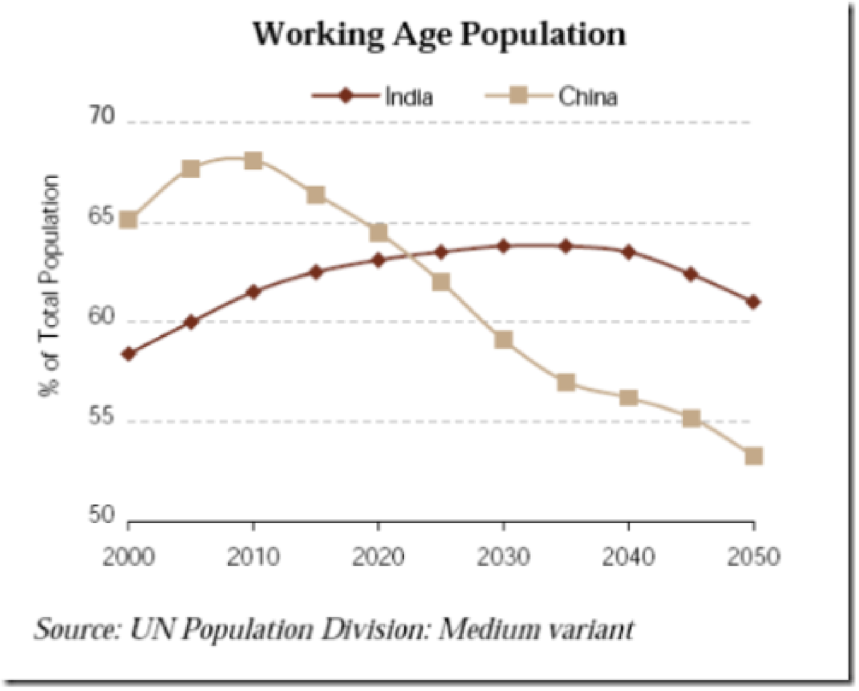

स्रोत : संयुक्त राष्ट्र, जनसंख्या प्रभाग : मध्यम संस्करण

सामाजिक-आर्थिक इंजीनियरिंग के अनुसार, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस अवधारणा को स्वीकार किया है कि 'एक अच्छी तरह से शिक्षित युवा श्रमजीवी देश' किसी भी सकारात्मक ऊँचाईयों तक पहुंचा सकता है। हम वर्तमान में 2030 तक शहरी जनसंख्या का 41% श्रम बल में वृद्धि करके लाभप्रद स्थिति में खड़े हैं।

यहाँ चित्र में भारत और चीन के बीच क्रियाशील जनसंख्या में काफी अन्तर दिख रहा है। जहाँ एक तरफ वर्ष 2000 में चीन के 65% के मुकाबले भारत 58% स्तर पर था वहीं 2010 में यह स्तर चीन में 72% तथा भारत में 62% था। अनुमान के अनुसार 2010 के पश्चात चीन की क्रियाशील जनसंख्या में तेजी से तथा निरन्तर कमी आएगी। जो कि कम से कम 2050 तक जारी हरेगी। वहीं दूसरी ओर भारत में यह गिरावट का स्तर 2035 के आस-पास प्रारम्भ होगा। तब तक भारत में विकास की वर्तमान गति निरन्तरता से सुनिश्चित हो सकती है।

विन-ली अब तक अपने नए शोध पत्र के लिए काफी विचार एकत्रित कर चुका था। तथा अपने विश्वविद्यालय के छात्रों को कक्षा के लिए संदेश भी भेज चुका था। उसने कुछ पुराने दस्तावेज और अखबार की कतरनों को एकत्रित किया और कॉलेज के लिए प्रस्थान किया।

References

- *China Statistical Yearbook - 2014.*
- *National Population Statistics*, National Bureau of Statistics (China).
- *World Population Prospects: The 2004 Revision*, United Nations.
- *Report on China*, Department of Economics and Social Affairs, United Nations.
- www.stats.gov.cn

प्रतिदर्श / नमूना प्रश्न

1. 'एकल बालक की नीति विभीषिका चीनी समाज में गहरे घाव छोड़ जाती है' दिए गए कथन का न्याय संगत औचित्य दे?
2. 'चीन ने अपनी जनसंख्या नियंत्रण नीति के क्रियान्वयन में एकल बालक नीति का समुचित प्रयोग किया है' किन कारणवश अब इस नीति का अन्त किया जा रहा है व्याख्या करें।

अंक योजना

1. दिया गया कथन निम्न बिन्दुओं से साबित हो सकता है।
   - चीनी अधिकारियों द्वारा एकल बालक नीति का बलपूर्वक क्रियान्वयन करना।
   - लाखों परिवारों तथा दम्पत्तियों के जीवन में भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक रिक्त स्थान की पूर्ति असम्भव है।?
   - कोई अन्य मान्य उत्तर

   (छात्रों द्वारा समुचित विवरण आवश्यक है।)
2. निम्न में से कोई दो कारणों की व्याख्या।
   - बढ़ती हुई बुर्जुग जनसंख्या
   - विषम लिंग अनुपात
   - 4-2-1 की समस्या
   - श्रमजीवी जनसंख्या में कमी
   - कोई अन्य मान्य उत्तर

   (छात्रों द्वारा समुचित विवरण आवश्यक है।)

मुक्त पाठ–आधारित मूल्यांकन 2016–2017

अर्थशास्त्र (030) कक्षा–ग्यारहवीं

विषय 2 : आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी–निवेश (एफ.डी.आई.) की भूमिका

शिक्षण उद्देश्य

छात्र सक्षम हो पाएँगे :

- एक देश के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका का मूल्यांकन करने में।
- चीन के विकास में एफ.डी.आई. की भूमिका की सराहना करने में।
- चीन और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी–निवेश की सीमा को समझने में।
- भारत के अलग–अलग राज्यों में एफ.डी.आई. की भूमिका तथा विशेष प्रभाव की तुलना करने में।

अध्यापक हेतु नोट

शिक्षकों और छात्रों के लिए ध्यान देने योग्य तथ्य। यह सामग्री छः भागों में लिखी गई है:

- आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी–निवेश की भूमिका।
- विकसित अथवा विकासशील अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव।
- चीन के विकास की कहानी।
- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका।
- एफ.डी.आई. के शीर्ष 10 स्थलों में क्षेत्रक–अनुसार विशेष विकास का उल्लेख।

मुक्त पाठ–आधारित मूल्यांकन 2016–2017

अर्थशास्त्र (030) कक्षा–ग्यारहवीं

विषय–2 : आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी–निवेश (एफ.डी.आई.) की भूमिका

सारांश

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई) एक ऐसा निवेश है जो किसी देश की एक कंपनी या एक इकाई के द्वारा किया जाता है या किसी अन्य देश में स्थित एक ईकाई के द्वारा किया जाता है। यह एक अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। पिछली सदी के दौरान कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एफ.डी.आई. की मदद से अपने विकास के लिए जो मंच मिला है उससे वह देश अधिक आर्थिक ऊंचाईयों पर पहुंचें हैं। यह पाठ न केवल छात्रों को एफ.डी.आई. का अर्थ समझाएगा अपितु चीन और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था के विकास पर खास जोर देते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के द्वारा निभाई गई भूमिका का अर्थ समझाएगा।

प्रत्यक्ष विदशी निवेश मेजबान देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। पिछले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सहायता से कई मेज़बान देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अपनी आर्थिक स्थिति में और सुधार करने के लिए मदद मिली है। पिछले 25 वर्षों में इस प्रवृत्ति ने स्वयं को साबित किया है। किसी भी प्रकार का विदेशी निवेश एक देश की अर्थव्यवस्था में पूंजी ज्ञान और तकनीकी संसाधनों को जुटाता है। यह देखा गया है कि आर्थिक स्थिरता पाने के लिए आर्थिक रूप से अविकसित तथा विकासशील देश वित्तीय सहायता के लिए विकसित देशों पर निर्भर करते हैं। आर्थिक रूप से विकसित देश, इन देशों में निवेश करके इन देशों की मदद कर सकते हैं।

इससे यह अविकसित तथा विकासशील देश अपने स्वयं के अनुसंधान और विकास के आधार पर देश के तकनीकी विकास में योगदान कर सकते हैं। यह सहायक है क्योंकि, अधिकांश ऐसे देश जो अपने स्तर पर देश के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के संदर्भ में अपने इन कार्यो को करने में सक्षम नहीं हैं, वह भी अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं जिससे वह आर्थिक दृष्टि से और अधिक सक्षम हो सकते हैं। कई बार यह सहायता प्रौद्योगिकी के रूप में भी दी जा सकती है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है।

Source: Moneycontrol.com

चीन में एफ.डी.आई.

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन चीन की आर्थिक सुधार की योजना प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। 1970 में 'ड़ेंग जियाओपिंग' के शासनकाल में चीन ने विदेशी निवेशकों को अपने क्षेत्र में आंशिक रूप से निवेश करने की अनुमति दी। इसने धीरे-धीरे विदेशी कारोबार के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जिसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बड़ी राशि को आकर्षित किया। एफ.डी.आई. के प्रति चीन की नीतियों को मोटे तौर पर तीन चरणों में अनुभव किया गया है।

क) प्रारंभिक चरण (जुलाई 1979 के बाद) क्रमिक और सीमित उद्घाटन।

ख) सतत् विकास के चरण (1986-91) प्राथमिकता के आधार पर अवसर दिया जाना।

ग) उच्च विकास की अवधि (1992 के बाद) विशिष्ट उद्देश्यों के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना।

सरकार ने अपनी सरल नीतियों का उपयोग करके विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) की स्थापना की है जो निर्यात आधारित सेक्टरों में एफ.डी.आई. के प्रवाह को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। विदेशी निवेशकों को प्राथमिक कर प्रणाली, उत्पादों और उपकरणों को आयात कराने की स्वतंत्रता और सरल लाइसेंसिंग प्रक्रिया जैसी सुविधाएँ दी गई व अतिरिक्त कर-लाभ भी उपलब्ध कराए गए। एफ.डी.आई. को कृषि, ऊर्जा, परिवहन और दूरसंचार के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया गया।

आर्थिक सुधारों के कारण अब विदेशी निवेशकों को चीन में निवेश करने में 2002 के शुरू में विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश पाने में विश्वास हो गया था। अब देश के निवेश के अवसरों और विशाल होते

घरेलू बाजार के आकर्षण के कारण चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो अब संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ ही पीछे है। अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रदर्शन के कारण चीन अत्यधिक एफ.डी. आई. निवेश आकर्षित कर पा रहा है और इसका श्रेय उसके द्वारा बनाई गई विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) योजना को जाता है, जो कि खास रूप से निर्यात क्षेत्र में लागू की गई है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसका केन्द्र बिन्दु बुनियादी ढांचा और तुलनात्मक लाभ है जो कम श्रम लागत से उत्पन्न होता है। जब भी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलना की गई है, यह देखा गया है कि नीतियाँ आम हैं, लेकिन चीन कृषि क्षेत्र में विशेष छूट के कारण सबसे आगे निकल पाया है।

भारत का अनुभव

1991 तक भारत ने अपनी आयात प्रतिस्थापन रणनीति और आत्म निर्भरता की वजह से एफ.डी.आई. नीति के संदर्भ में एक सतर्क दृष्टिकोण का पालन किया। विदेशी सहयोग के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उच्च प्रौद्योगिकी और उच्च प्राथमिकताओं वाले सार्वजनिक क्षेत्रों में ही स्वागत किया गया। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) की स्थापना की, चयनात्मक उदार नीति की रचना की तथा इन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया लेकिन इन उपायों से भी निर्यात की प्रतिस्पर्धा में कोई खास सहायता नहीं मिली क्योंकि भारत आरंभ से ही अत्यधिक सतर्क देश रहा। यह संरचनात्मक आर्थिक सुधार लगभग सभी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में शुरू हुए थे। उसकी तुलना में 24 जुलाई, 1991 से विदेशी निवेश के लिए भारत के दृष्टिकोण में एक बड़ा परिवर्तन आया है।

1991 में निम्नलिखित कारणों की वजह से आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी–

- भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 8.4 प्रतिशत था। हमारी अर्थव्यवस्था कर्ज के जाल में जकड़ी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अंततः ऋण अग्रिम करने के लिए सहमति तो व्यक्त की लेकिन जोर देकर कहा कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों को लागू करना चाहिए।
- विदेशी ऋण? सकल घरेलू उत्पाद का 23 प्रतिशत बढ़ गया।
- विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट।
- सार्वजनिक क्षेत्र की विफलता।
- बढ़ती कीमतें।

भारत ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण और सुधार कार्यक्रमों को आरम्भ करने पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य था अपने विकास की संभावनाओं को बढ़ाना और लक्ष्य था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होना। औद्योगिक नीति में किए गए सुधारों ने जहाँ एक तरफ धीरे-धीरे निवेश परियोजनाओं से प्रतिबंध हटा दिया और व्यापार का विस्तार किया वहीं दूसरी ओर विदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि हुई और उसके लिए अधिक राशि मिल पाई। इन प्रयासों को बढ़ावा एक बड़ी संख्या में अधिनियमों के लागू करने से मिला जिससे विदेशी मुद्रा व्यवहार में परिवर्तन लाना सहज हो गया।

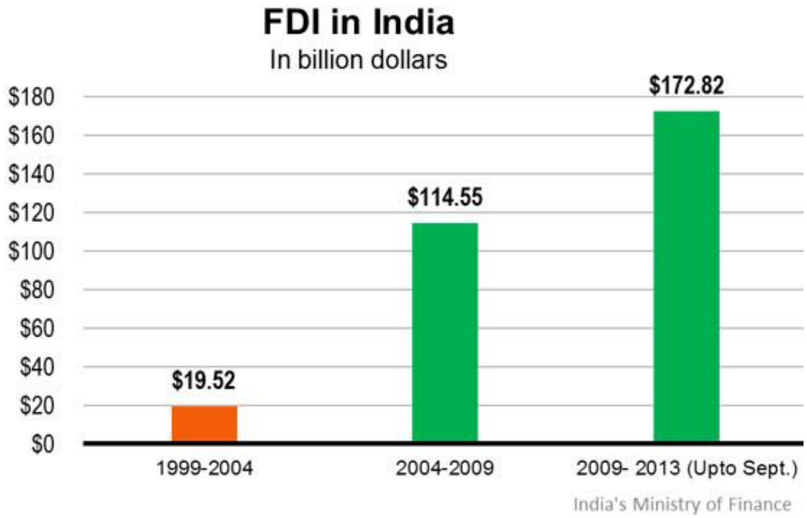

Source: Ministry of Finance (Govt. of India)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह भारत में दो मार्गों द्वारा संभव है

1. **स्वचालित मार्ग :** इस मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी, निवेश, सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदक के बिना संभव है। उदारीकरण के बाद के दौर में भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की एक बड़ी राशि को आकर्षित किया है। भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सभी क्षेत्रों में बढ़ावा दे रहा है, बस कुछ को छोड़कर जहाँ एक सीमा से परे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। उदारीकरण के बाद से इसकी भूमिका काफी बदल गई है। एफ.डी.आई. नीति के प्रगतिशील उदारीकरण ने एकीकृत नागरिक प्रशासन विभाग जैसे नए क्षेत्रों के उद्घाटन के साथ निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है। स्वचालित मार्ग के तहत एफ.डी.आई. को सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा किसी भी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। निवेशकों को केवल आवक-विप्रेषण प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में सूचित करना

है या फिर विदेशी निवेशकों के लिए शेयर जारी करनेके 30 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेजों को उस कार्यालय में जमा करवाना है।

2. **सरकारी मार्ग :** इस मार्ग में सरकार द्वारा पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इस मार्ग में देखरेख की जिम्मेदारी विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को दी गई है। अधिकतर क्षेत्रों में भारत बहुमत के साथ प्रत्यक्ष विदशी निवेश का एक प्रमुख प्राप्तकर्ता रहा है। इस मार्ग के तहत, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) द्वारा प्रस्तावों पर एक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से विचार किया जाता है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) की सिफारिशों पर ही विदेशी निवेश व विदेशी तकनीकी सहयोग से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक संस्था, स्वाचालित मार्ग के अंतर्गत आने वाले निवेश प्रस्तावों और फेमा से संबंधित मामलों को निपटा रही है, जबकि सरकार की मंजूरी मार्ग से किए जाने वाले निवेश और एफ.डी.आई. नीति से जुड़े मुद्दों को अपनी निम्नलिखित तीन संस्थाओं के माध्यम से संभालती है।

1. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी)
2. औद्योगिक सहायता सचिवालय (एस.आई.ए.)
3. विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.डब्ल्यू.ए.)

भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि देखी गई है, जो कि अप्रैल 2015 में US $ 3509 से जनवरी 2016 में US $ 4413 पाई गई और जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है।

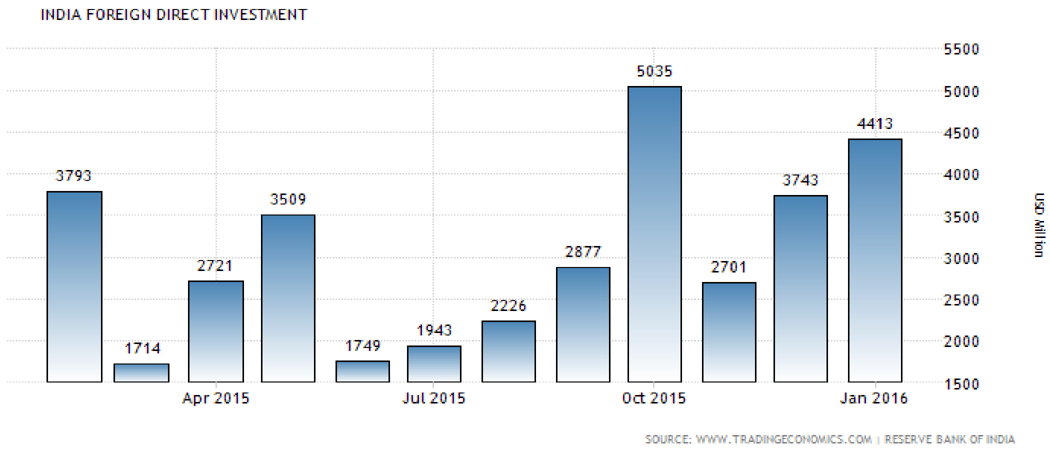

Source: Reserve Bank of India

उदारीकरण की शुरूआत के बाद से देश ने अपनी जबरदस्त वृद्धि क्षमता के कारण सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह में एक ऊंचे उछाल का अनुभव किया। 1991 से इस क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) को बढ़ावा देने वाले शीर्ष दस क्षेत्रों में के बीच में स्थान दिया गया है। इस क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, नियामक सुधारों की स्थापना, बढ़ते भारतीय बाजार और कुशल कार्य बल की उपलब्धता आदि कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।

Figure 1: Trends in Foreign Direct Investment Inflows in India 1990-91 to 2009-10

Source: Reserve Bank of India

अप्रैल 2000 से जुलाई 2014 तक भारत में एफ.डी.आई. प्रवाह करने वाले शीर्ष 10 देश जो दिखाई देते हैं, वे हैं- मॉरीशस, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, साइप्रस, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड।

क्षेत्रानुसार विश्लेषण : एफ.डी.आई. प्रवाह

दूरसंचार क्षेत्र : भारत में दूरसंचार क्षेत्र एक आश्चर्यजनक गति से बढ़ रहा है जो विश्व भर में सबसे बड़े संचार नेटवर्क में से एक है जिसमें 125 से अधिक मिलियन टेलीफोन नेटवर्क है। दूरसंचार उद्योग जिसमें कि दूरसंचार, सेलुलर मोबाइल और बुनियादी टेलीफोन सेवाएँ शामिल हैं उसे 1991 से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने शीर्ष दस क्षेत्रों के बीच स्थान दिया जा सकता है। दूरसंचार क्षेत्र में एफ.डी.आई. प्रवाह का मुख्य कारण भारत में बढ़ती मांग और निजी क्षेत्र की भागीदारी है। दूर-संचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से 74% तक बढ़ा दिया है।

निर्माण क्षेत्र : इस क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाले शीर्ष 5 देशों में से एक है। इसमें आवास, व्यावसायिक परिसर, होटल, रिसॉर्ट, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और बुनियादी ढांचा भी शामिल है इस क्षेत्र के लिए एफ.डी.आई. को अनुमति स्वचालित मार्ग के तहत दी जाती है। 2000 से 2014 के दौरान निर्माण गतिविधियों में काफ़ी राशि को आकर्षित किया। 2005 की शुरूआत से निर्माण गतिविधियों के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के अंतर्गत अचानक भारी उछाल देखा गया है।

ऑटोमोबाइल उद्योग : भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह गति से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दी गई है और वे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो ऑटोमोबाइल उद्योग के द्वारा एशिया में अपना आधार स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए भारत एक प्रमुख गंतव्य बनता जा रहा है इसका कारण वो बुनियादी लाभ है जो भारत प्रदान कर सकता है। जैसे– उन्नत प्रौ़द्योगिकी लागत प्रभावशीलता, कुशल, मानव शक्ति और सबसे महत्वपूर्ण है बढ़ती मांग।

विद्युत क्षेत्र : इस क्षेत्र ने 1991 से 1999 की अवधि के दौरान काफी मात्रा में एफ.डी.आई. को आकर्षित किया। निवेश पर अधिक रिटर्न और बाजार का विशाल आकार इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को बढ़ाने में दो महत्वपूर्ण कारक है। परमाणु ऊर्जा को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के बिजली उत्पादन में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफ.डी.आई. की अनुमति दी गई है।

धातुकर्म उद्योग : 1991 के बाद धातुकर्म उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहुत कम नजर आंका गया है। इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदशेी निवेश नवीनतम नवीनतम प्रौद्योगिकी लाने के लिए मदद कर सकता है लेकिन इस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभुत्व के कारण ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं मिल सका। भारत दुनिया भर के शीर्ष दस एल्युमीनियिम और स्टील आपूर्तिकर्ताओं में शुमार है तथा दुनियाभर में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा निर्माता है।

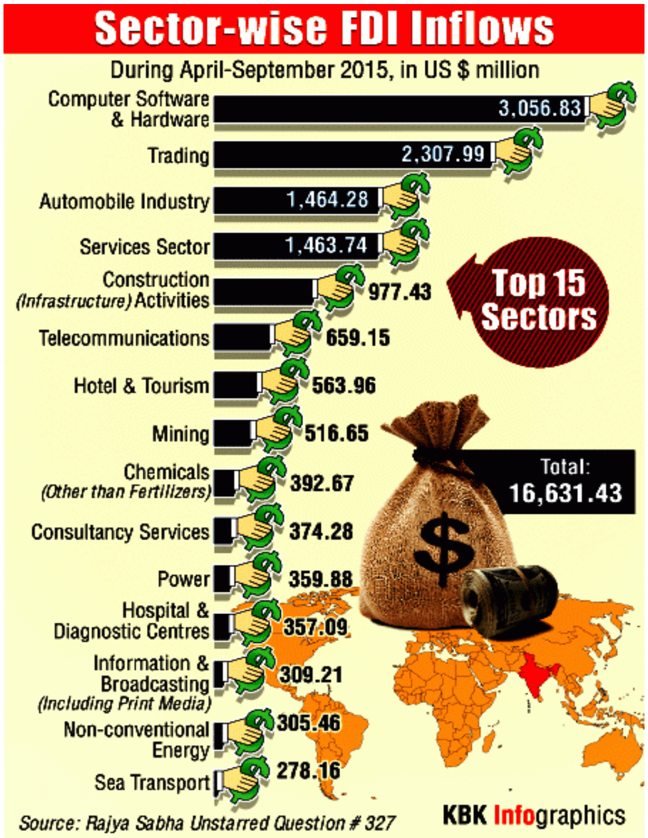

Source: Ministry of Finance (Govt. of India)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस : वर्ष 2014 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह शुरू हुआ है। उसी समय से इस क्षेत्र में प्रवाह पूर्ण अर्थों में बढ़े हैं और यह क्षेत्र शीर्षस्थ श्रेणी में अपने लिए स्थान बना पाया है। हालांकि भारत सरकार ने एफ.डी.आई प्रवाह को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग तहत सौ प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की बढ़ती हुई मांग ने इस क्षेत्र में निवेश को जरूरी बना दिया है।

रसायनिक उद्योग : 1980 और 1980 के दशक में उर्वरकों की तुलना में अन्य रसायनों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के एक महत्वपूर्ण भाग को आकर्षित किया है भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन की वजह से 1990 से लेकर पिछले कुछ वर्षों में भारत में रसायनिक उद्योग के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह में वृद्धि हुई है। भारत में स्वचालित मार्ग के तहत रसायन में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। डाउ केमिकटस, बी.ए.एस.एफ. डूपोंट और बायर आदि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ हें जो रसायन उद्योग में कार्यरत है।

व्यापारिक क्षेत्र : व्यापरिक क्षेत्र, 2005 तक एक पिछड़ा निवेश स्वरूप दिखाता है, लेकिन 2006 से प्रवाही में एक घातीय वृद्धि आई है। एंकर इलैक्ट्रिकल्स, एस्सिलर प्रा. लिमिटेड, मटरी कमोडिटी एक्साजिज एंड इंडिया लिमिटेड, मेट्रो कैश एंड कैरी प्रा. लिमिटेड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाहों को प्राप्त करने वाली पाँच शीर्ष कंपनियाँ हैं।

होटल और पर्यटन उद्योग पिछले कुछ वर्षों से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि यह क्षेत्र देश के विभिन्न हिस्सों से विदेशी के साथ ही घरेलू पर्यटकों के माध्यम से बड़े राजस्व ला पा रही है। स्वचालित मार्ग के तहत होटल और पर्यटन में 100% एफ.डी.आई. की अनुमति दी गई है। इससे देश के विभिन्न भागों में एफ.डी.आई. प्रवाह में बढ़ोत्तरी देखी गई है जो कि 1991 से 1999 के दौरान US $ 91.13 मिलियन से बढ़कर 2000 से 2014 के दौरान US $ 7607.01 मिलियन तक जा पहुँची है, हाल के वर्षों भारत से बाहर जाने वाले पर्यटकों में भी वृद्धि हुई है क्योंकि अधिक से अधिक भारतीयों के विदेश दौरे लगने लगे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटरों ने भारत से ही संचालन शुरू कर दिए हैं ताकि वे भारत में विदेशी दौरों के बढ़ते हुए बाजार पर नियंत्रण कर सके। इसके कारण भारत में होटल और पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। 2009 में विश्व बैंक ने अपना नवीनतम प्रकाशन 'सीमाओं के पार निवेश' शीर्षक से प्रकाशित किया। इसके किए गए सर्वेक्षण ने चार संकेतक माने हैं–

1. **सीमाओं के पार निवेश :** वह डिग्री जिसमें एक देश, विदेशी कंपनियों को स्थानीय कंपनियों का अधिग्रहण करने की अनुमति देता है।
2. **एक विदेशी व्यापार की शुरूआत करना :** एक विदेशी कंपनी स्थापित करने में समय, प्रक्रियाओं और नियमों की आवश्यकता।
3. **औद्योगिक भूमि पाना :** विदेशी कंपनियों के भूमि खरीदने तथा भूमि को कुछ समय के लिए किराये पर लेने के कदम व कानूनी विकल्प।
4. **वाणिज्यिक विवादों के निर्णय हेतु :** वे सूचक जो कानूनों की ताकत का आंकलन करते हैं और न्यायपालिका कहाँ तक उनका समर्थन करती है और उन्हें सहज बनाती है।

(17 जनवरी, 2011 को जारी) UNCTAD's वैश्विक निवेश रूझान के आंकलन के अनुसार उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सुधारते हुए सूक्ष्म आर्थिक हालात जिन्होंने सम्मिलित लाभ को नया उछाल दिया, बेहतर शेयर बाजार के उतार–चढ़ाव और बढ़ते कारोबारी विश्वास ने दुनियाभर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की

संभावनाओं को अच्छे संकेत दिए। UNCTAD के अनुसार इन अनुकूल सुधारों के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह में विकासशील देशों की हिस्सेदारी 50 फीसदी से भी अधिक बढ़ गई और मजबूत विकास की संभावनाओं के कारण इनमें और बढ़ोत्तरी की संभावना है। अपने घरेलू आर्थिक प्रदर्शन के कारण भारत ने भी अत्यधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह प्राप्त किया। एफ.डी.आई. प्रवाहों में उल्लेखनीय वृद्धि बताती है कि यह सब अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रभाव से परिलक्षित होता है। क्षेत्र विशेष नियमों और विनियिमों का अनुपालन करते हुए धीरे–धीरे एफ.डी.आई. को लगभग सभी क्षेत्रों में अनुमति दी गई जिसमें कुछ क्षेत्रों को तकनीकी महत्व की बुनियाद पर छोड़ दिया गया।

चीन कृषि के क्षेत्र में 100% एफ.डी.आई. को अनुमति देता है परन्तु मीडिया के क्षेत्र में एफ.डी.आई. पूरी तरह से निषेध है। दूसरी ओर भारत में खनन तेल और गैस, बिजली और स्वास्थ्य तथा कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में 100% तक विदेशी स्वामित्व की अनुमति है।

मेक इन इंडिया : भारत सरकार ने यह पहल बहुराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में ही उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए की है।

Source: Ministry of Commerce, Government of India

मेक इन इंडिया के उद्देश्य :

- रोजगार सृजन और कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित करना।
- उच्च गुणवत्ता मानकों तक पहुँचना।
- पर्यावरण पर प्रभाव को न्यूनतम करना।
- भारत में विकास और निवेश को आकर्षित करना।

मेक इन इंडिया के तहत ऑटोमोबाइल, विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, निर्माण, रक्षा, विनिर्माण, विद्युत मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, चमड़ा, मीडिया और मनोरंजन, खनन, तेल और गैस, बंदरगाह और शिपिंग, रेलवे, अक्षय ऊर्जा, सड़क और परिधान, ताप विद्युत, पर्यटन, कल्याण आदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने के सबसे प्रमुख क्षेत्र हैं। अंतरिक्ष (74%), रक्षा (49%) और मीडिया (26%) को छोड़कर बाकी इन सभी क्षेत्रों में 100% FDI की अनुमति है।

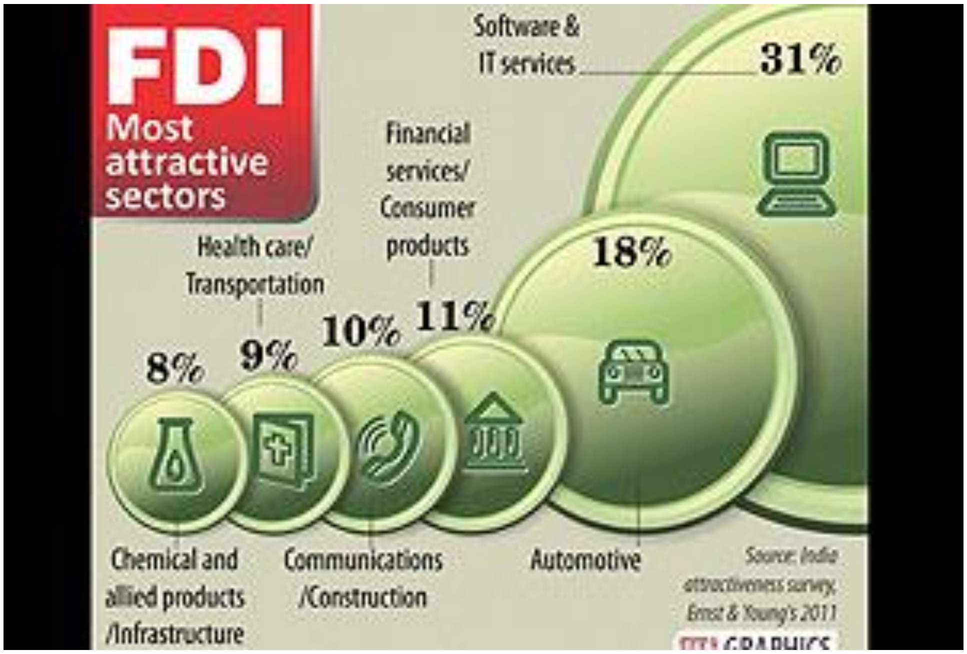

Source: Indian Express (website)

इस कार्यक्रम की दिक्षा के बाद भारत विश्व निवेश के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरेगा।

इस कार्यक्रम के लागू किये जाने से पहले ही विदेशी इक्विटी कैप्स निश्चित थे, लाइसेंस ऑनलाईन उपलब्ध थे और उनकी वैद्यता तीन वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। 2014 में रक्षा के क्षेत्र में 49% FDI और रेलवे के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी गई। सितम्बर 2014 से नवम्बर 2015 के बीच भारत सरकार ने US $ 18 अरब की कीमत के प्रस्ताव प्राप्त किये। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए जो कि 2020 तक US $ 400 अरब तक जा सकती है, ऐसा कहा जा सकता है कि भारत में एक संभावित विनिर्माण केन्द्र बनने की पूरी क्षमता है। स्पाइस समूह ने उत्तर प्रदेश में, सैमसंग ने नोएडा में, हिताची ने चेन्नई में, हवाई ने बैंगलोर में और जिओमी ने आंध्र प्रदेश में निवेश किया है और भारत में अपनी इकाईयों की स्थापना की है।

क्र. सं.	शहर	उद्योग	कारण
1.	बैंगलोर	आई.टी. सेक्टर	बुनियादी ढांचा और सक्षम कार्यबल
2.	दिल्ली	सेवा उद्योग आई.टी. उद्योग	राजधानी में बेहतर सुविधाएँ होने के नाते और सक्षम कार्यबल परामर्श
3.	पुणे	आई.टी. सेक्टर सॉफ्टवेयर	बेहतर सुविधाएँ और कर्मचारियों की संख्या विनिर्माण
4.	मुम्बई	सेवाएँ, विनिर्माण, ऊर्जा परिवहन और बैंकिंग	विशेष आर्थिक क्षेत्र, वित्तीय पूंजी जैव प्रौद्योगिकी की स्थापना, ई–गवर्नेंस
5.	चेन्नई	ऑटोमोबाइल सेक्टर	सरकारी नीतियाँ
6.	हैदराबाद	आई.टी. सेक्टर	विशेष आर्थिक क्षेत्र
7.	कोलकाता	आई.टी. सॉफ्टवेयर	विशेष आर्थिक क्षेत्र और बेहतर बुनियादी ढांचे
8.	अहमदाबाद	निर्यात और आभूषण	साबरमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना
9.	नागपुर	विद्युत वितरण	सार्वजनिक परिवहन
10.	जयपुर	पारंपरिक और हाथ से बने पत्थर के आभूषण	स्थानीय कुटीर उद्योग

नवम्बर 2015 को रेल मंत्रालय ने US $ 5.9 अरब के औपचारिक समझौते पर एल्सटाम तथा जी.ई. परिवहन के साथ हस्ताक्षर किऐ जिसके तहत वह बिहार के मधेपुरा तथा महौरा के लाकोमोटिव निर्माण कारखानों करें स्थापित कर पायेगा। दिसम्बर 2015 में क्वालकॉम ने "भारत में डिजाइन" कार्यक्रम की घोषणा की, जिससे कि वे 10 भारतीय हार्डवेयर कम्पनियां जो अपने नवीन संसाधनों के साथ ऊंचाईयों को छू सकती है, उनको तैयार किया जा सके। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कंपनी बैंगलोर में एक इनोवेशन लैब की स्थापना करेगी जिसमें चयनित कंपनियों को तकनीकी तथा इंजीनियरिंग समर्थन प्रदान किया जायेगा। इसी माह में माइक्रोमैक्स ने US $ 45 मिलियन की लागत से राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तीन नई विनिर्माण इकाईयाँ स्थापित करने की घोषणा की। ये यूनिट 2016 में कामकाज प्रारंभ करेगी। प्रत्येक यूनिट 3000 से 3500 रोजगार अवसर पैदा करेगी।

दिसम्बर 2015 में जापान के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के बाद यह घोषणा की गई की जापान US $ 12 अरब मेक इन इंडिया के लिए विशेष वित्त सुविधा के रूप में प्रदान करेगा। दिसम्बर 2015 में, फोन निर्माता विवो मोबाइल ग्रेटर नोएडा में स्मार्ट फोन का उत्पादन प्रारंभ कर चुका है, इस संयत्र में 2200 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। दिसम्बर 2015 में प्रधानमंत्री के रूस के दौरे में रक्षा–समझौते पर हस्ताक्षर किऐ गए जिसके अंतर्गत कामोब के ए–226 नामक बहु भूमिका हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में होना निर्धारित हुआ है। व्यापक रूप से यह पहला ऐसा समझौता है जो कि वास्तव में मेक इन इंडिया अभियान के तहत हस्ताक्षर किया गया है।

संदर्भ सूची

- www.tradingeconomies.com
- ग्लोबल इनवेस्टमेंट ट्रेडंस मॉनीटर, A report by UNCTAD
- www.bojournal.com
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में चीन (एफ.डी.आई.), जॉन हेनली
- sectorwise FDI inflows into India, JBM & SSR, Vol 4 No. 1, Jan 2015
- www:businessmapsofindia.com (चीन और भारत का एक तुलनात्मक अध्ययन)
- FDI in India, FAB School (2013-15)
- भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के प्रभाव–एक वर्किंग पेपर, विश्व बैंक।

प्रतिदर्श / नमूना प्रश्न

1. भारत और चीन में एफ.डी.आई. प्रवाह की तुलना कीजिए।
2. एफ.डी.आई. का प्रवाह बढ़ाने के लिए उत्तर उदारीकरण के साधनों को भारत में क्यों लागू किया गया?

अंक योजना

1. चीन में एफ.डी.आई. प्रवाह ने 3 चरणों में जगह ली–प्रारंभिक चरण में, सतत विकास के चरण और उच्च विकास दर।
2. सार्वजनिक क्षेत्र की विफलता, बहुत ही उच्च राजकोषीय घाटे, विभाग जाल और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण नई आर्थिक नीति को कार्यान्वयन करने की आवश्यकता पड़ी।

OTBA

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिक्षा केन्द्र, 2, समुदाय भवन, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092, भारत
फोन नं. : 011-22509256-57 • वेबसाइट : www.cbse.nic.in